हरियाणा राजभवन से कमीशन एजेंट की छुट्टी

चंडीगढ (म.मो.) ए डी सी की वर्दी पहन कर करीब 10 साल तक हरियाणा भवन में गवर्नरों की दलाली करने वाले जगप्रवेश दहिया की अब वहां से छुट्टी हो गयी है। उनके स्थान पर 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी सतीश बालान को नियुक्त किया गया। बालान अब तक मेवात के एसपी थे।

हरियाणा-पंजाब के इतिहास में शायद यह पहला मौका था जब आईपीएस के स्थान पर किसी एचपीएस अधिकारी को गवर्नर का एडीसी (पुलिस) लगाया गया हो। इतना ही नहीं 28 फ़रवरी 2013 को रिटायर होने के बावजूद भी उनकी यह नौकरी चलती रही और इतने लम्बे समय तक इस पद पर रहने का कभी न टूटने वाला रिकार्ड कायम कर दिया।

दरअसल इसके पीछे गवर्नर के पद पर तैनात होने वालों का गिरता स्तर है। कहां तो बी.एन. चक्रवर्ती जैसे ऊंचे दर्जे के गवर्नर इस राज्य ने देखे और फ़िर बाद में जब पतन होने लगा तो तपासे और मंडल जैसे गवर्नर भी देखने को मिले। लेकिन जगन्नाथ पहाड़िया तो पतन की सीमा लांघ कर सबसे आगे निकल गये। यह उनका ही व्यक्तित्व था जो एक डीएसपी स्तर के अधिकारी जगप्रवेश की ऊंगलियों पर नाचते थे। किसी का उद्घाटन करना हो, किसी को नौकरी लगवाना, तबादला करवाना या छुटी हुई नौकरी दोबारा दिलवानी हो, सबकी सेटिंग जगप्रवेश के माध्यम से होती थी।

गवर्नर की नकेल जगप्रवेश के हाथों में होने के चलते बड़े-बड़े (डीजीपी स्तर तक के) अधिकारी उन्हें सलाम करते थे। करें भी क्यों न जब गवर्नर से कोई काम निकलवाना हो तो उनके एजेंट को सलाम तो करना ही पड़ेगा। काम निकलवाने के किस्से तो इतने अधिक हैं कि पूरा अखबार ही छोटा पड़ जायेगा; परन्तु एक किस्सा विवेक पदम का खास गौरतलब है। विवेक पदम एचसीएस अधिकारी था। अपनी गुड़गांव पोस्टिंग के दौरान अच्छा मोटा घोटाला कर दिया। राज्य सरकार ने विधिवत जांच करके उन्हें 11 फ़रवरी 2010 को नौकरी से बरखास्त कर दिया। जगप्रवेश के माध्यम से सैटिंग करके 9.8.10 को गवर्नर को मैमोरियल दिया गया। गवर्नर ने अपने विशेषाधिकार का दुरूपयोग करते हुए विवेक पदम को 28 नवम्बर 2014 को नौकरी में बहाल कर दिया। सज़ा के तौर पर उनके मात्र 3 इन्क्रीमेंट काटे गये। झूठ-सच का तो पता नहीं लेकिन इस बहाली को लेकर राज्य भर की अफ़सरशाही में एक करोड़ के लेनदेन का चर्चा काफ़ी दिन तक चला। मज़े की बात तो यह है कि पहाड़िया के बाद बतौर गवर्नर आये कप्तान सिंह सोलंकी को भी जगप्रवेश खूब भाये, लेकिन अब आगे और कितना सेवा विस्तार देते जगप्रवेश को।

धंधेबाज़ों को नहीं सुहाये सी पी सुभाष यादव

फ़रीदाबाद (म.मो.) 11 नवम्बर 2014 को इस शहर की पुलिस कमान सम्भालने वाले सी पी सुभाष यादव को मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 10 मार्च को यहां से बतौर आई जी करनाल के लिये रवाना कर दिया। करीब सवा साल के अपने इस छोटे से कार्यकाल में यादव ने गली-गली में शराब बेचने व जुआ सट्टा चलाने वालों के विरुद्ध काफ़ी ज़ोरदार अभियान चलाये। पुलिस की नस-नस में घुस चुकी रिश्वतखोरी व कानूनी खामियों के चलते वे इस काम में बेशक पूरी तरह सफ़ल नहीं हो सके, लेकिन फ़िर भी उनका अभियान जारी रहा। शहर भर के शातिर सज़ायाफ़्ता बदमाश जो अपनी दहशत के बूते शहरियों से अवैध वसूलियां करते थे, इन दिनों नज़र आने बंद हो गये थे। इसके अलावा बदमाशों को पालने वाले पनाहग़ार बिलों में घुस गये थे।

सर्वविदित है कि कोई भी बदमाश पुलिस की मर्जी के बिना बदमाशी नहीं कर सकता। लेकिन यही पुलिस अपनी स्वीकृति न देवे तो फ़िर बदमाश इसके लिये उन राजनेताओं पर दबाव बनाते हैं जिनको चुनाव जिताने में उन्होंने मदद की होती है। जो पुलिस अधिकारी इन नेताओं का दबाव नहीं मानता उससे ये नेता नाराज़ हो जाते हैं, उसकी मुखालफ़त करते हैं, तरह-तरह के आरोप लगाते हैं तथा उसके तबादले के लिये राजनीतिक दबाव बनाते हैं। कुछ इसी तरह की परेशानी स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर को भी सी पी सुभाष यादव से रही। यद्यपि कई मौकों पर सी पी ने कृष्णपाल गूजर गिरोह की करतूतों को न केवल अनदेखा किया बल्कि उसे पुलिस सहयोग भी दिया जैसे कि सूरजकुंड थाना क्षेत्र में इरोज कम्पनी की करीब एक एकड़ ज़मीन पर बने क्लासिक गार्डन पर इस गिरोह का कब्ज़ा बहाल कराने में।

पुलिस चौकी 21 डी में इस गिरोह द्वारा मचाये गये उत्पात को अनदेखा करने का परिणाम थाना ओल्ड फ़रीदाबाद में बहुत भयंकर रूप से प्रकट हुआ। इससे बड़ी संख्या में गिरोह के लोग थाने में घुस आये थे और पुलिस से दो-दो हाथ करने लगे थे। जब पुलिस ने बल प्रयोग करने के साथ-साथ उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किये तो गिरोह के सरगना एवं सांसद कृष्णपाल जी भड़क गये। थाने के एसएचओ, डीसीपी व सीपी के तबादले व उनके विरुद्ध अन्य कड़ी कार्यवाही के लिये भरसक प्रयास किये। परिणामस्वरूप सीपी तो बचे रह गये बाकी दोनों पर तबादले की गाज गिरी।

सुभाष यादव से, विधायकों में सबसे ज़्यादा दुखी विपुल गोयल रहते थे। परन्तु गुजरते समय के साथ कृष्णपाल की चेलागिरी छोड़ कर जब विपुल ने अपने बूते खड़े होना सीख लिया तो इन्होंने सीपी से अपने सम्बन्ध मधुर बना लिये, सिर्फ़ इसलिये कि वे कृष्णपाल से अलग दिखें।

अति उच्च एवं विशवस्त सूत्रों की माने तो सुभाष यादव के तबादले में कृष्णपाल की भूमिका उतनी अधिक भी नहीं है जितनी समझी जा रही है। इन्हीं सूत्रों के मुताबिक इससे अधिक भूमिका अफ़सरशाही के उस डाकू गिरोह की है जो खुल्लर के नेतृत्व में खट्टर के चारों ओर घेरा डाले पड़ा है। इस शहर में बतौर नगर निगम आयुक्त रह चुके हरियाणा के भ्रष्टतम अफ़सरों में से एक खुल्लर को मनोहर लाल खट्टर, डाके मारने के लिये विशेष रूप से दिल्ली से उठा कर लाये हैं जहां वे केन्द्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर मक्खियां मार रहे थे। इस शहर में खुल्लर को लूटमार के लिये सुभाष यादव वांछित सहयोग नहीं दे पा रहे थे, इसलिये उन्होंने तथाकथित अति ईमानदार मुख्यमंत्री खट्टर के हाथों उनका तबादला करा दिया।

अब देखने वाली बात यह रह गयी है कि उनके स्थान पर आये हनीफ़ कुरैशी खुल्लर व कृष्णपाल को उनके काम-धन्धों में कितना सहयोग दे पायेंगे। अब तक की उनकी तैनातियों का रिकॉर्ड बताता है कि वे एक साफ़-सुथरी छवि के ईमानदार एवं दबंग अफ़सर रहे हैं। यह तो आने वाला समय ही बतायेगा कि वे अपनी छवि को तरजीह देते हैं या फ़रीदाबाद की तैनाती से चिपके रहने को।

विकलांग पुलिस को जरूरत है और विकलांगों की

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 29 फ़रवरी को ज़िले की पुलिस लाइन में परम्परानुसार सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों का सामूहिक विदाई समारोह आयोजित किया गया था। इसमें सेवानिवृत्त होने वालों के अतिरिक्त ज़िले के उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर चाय पार्टी व फ़ोटोग्राफ़ी आदि के बाद विदा होने वालों को कुछ उपहार आदि भी दिये जाते हैं।

उस दिन विदा होने वालों में ए.सी.पी. बल्लबगढ विष्णुदयाल भी उपस्थित थे। चाय व फ़ोटो आदि के बाद जब उन्हें उपहार दिये जाने लगे तो अजीब स्थिति उत्पन्न हो गयी। वैलफ़ेयर इन्सपेक्टर तो उन्हें उपहार पकड़ाये और ए सी पी पकड़े नहीं। कुछ देर चले इस ड्रामे को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान थे। ए सी पी का कहना था कि वे अभी रिटायर नहीं होंगे जबकि पुलिस रिकार्ड एवं आदेशों के अनुसार वे उस दिन रिटायर हो चुके थे। लेकिन इस ड्रामे का रहस्य अगले दिन यानी पहली मार्च को तब खुला जब पुलिस मुख्यालय चंडीगढ से उन्हें दो वर्ष के सेवा-विस्तार का एक पत्र मिल गया।

इस सेवा-विस्तार का आधार उनका विकलांग होना बताया गया है। बीसियों बरस पहले जब वे थानेदार थे तो दुर्घटनावश उनका दायां हाथ (कलाई से) रेल के नीचे आकर कट गया था। जैसे तैसे जान तो बच गयी और विशेष अनुकम्पा के तहत नौकरी भी। वरना फ़ौज और पुलिस बल में विकलांगों के लिये पुनर्वास की जगह ही होती नहीं। सेवा के दौरान विकलांग होने पर विकलांगता पेंशन देकर कर्मचारी को प्राय: सक्रिय सेवा से सेवानिवृत कर दिया जाता है। परन्तु, किसी बल में शायद यह पहला उदाहरण है जब किसी को विकलांगता के आधार पर सेवा-विस्तार और वह भी दो साल का दिया गया हो। अब तक बहादुरी मेडल पर तो एक वर्ष का सेवा-विस्तार मिलते देखा गया था, परन्तु विकलांगता के आधार पर सेवा-विस्तार कभी देखने-सुनने में नहीं आया।

यदि सरकार विकलांगों पर इतनी ही मेहरबान है तो नियमित भर्ती में भी विकलांगों का कोटा तय कर देना चाहिये। इससे विकलांग भी, पहले से ही विकलांग हो चुकी पुलिस की शोभा बढा सकेंगे। लगे हाथ सरकार को यह भी तय कर देना चाहिये कि कितने प्रतिशत विकलांगता पर कितने वर्ष का सेवा-विस्तार मिला करेगा; यानी कलाई तक हाथ कटने पर दो साल तो ऊंगुली कटने या पूरा हाथ अथवा टांग कटने पर कितने वर्ष का सेवा-विस्तार मिलेगा? गत माह हरियाणा भर में मची तबाही के दौरान राज्य पुलिस की विकलांगता तो वैसे भी सिद्ध हो ही चुकी है, ऐसे में यदि बिना हाथ या बिना पैर वालों को भी पुलिस में भर्ती कर लिया जाय तो क्या हर्ज है। हरियाणा विकलांग कल्याणा के मामले में भी नम्बर वन हो जायेगा।

संदर्भवश सुधी पाठक जान लें कि ए सी पी रैंक के अधिकारी को सेवानिवृत्त होने पर भविष्य निधि, ग्रेच्यूटी 6 माह की छुट्टियों के वेतन सहित करीब 50 लाख नकद तो मिलते ही हैं साथ में करीब 40 हज़ार मासिक पेंशन भी आयुपर्यन्त मिलती है। देखा जाय तो ये सारे लाभ इस वेतन से कहीं अधिक पड़ते हैं जो सरकार उसे आज दे रही है, यानी कि घर बैठे उसे वेतन से कहीं ज़्यादा मिलता है। इसके बावजूद भी जो कोई नौकरी से निवृत्त नहीं होना चाहता तो स्वत: सिद्ध है कि उसके इरादे सेवा की आड़ में मिलने वाले मेवे पर है।

मुकेश अंबानी के हित साधे गए हैपनिंग हरियाणा में

-वाई. के. रज्जन

हरियाणा में बीजेपी सरकार को आए हुए लगभग डेढ़ साल पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन राज्य में रामनाम की लूट मच गई है। अभी इस सरकार ने 7-8 मार्च को गुड़गांव में हैपनिंग हरियाणा के नाम से उद्योगपतियों का एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने प्रधानमंत्री की तर्ज पर कई देशों की यात्रा करके वहां के उद्योगपतियों को गुड़गांव सम्मेलन में आने का न्योता दिया। हालांकि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान राज्य में हुई हिंसा के दौरान इस सम्मेलन को टालने की सलाह मुख्यमंत्री को दी गई थी लेकिन खट्टर तो खट्टर वो भी मोदी के अंदाज में आ चुके हैं तो वो किसी की क्यों सुनते। सम्मेलन अपने तारीख पर हुआ। लेकिन इसकी आड़ में रिलायंस के हित साधने का मामला सामने आया है।

गुड़गांव के बहुत ही महंगे पांच सितारा होटल में हुए इस सम्मेलन पर राज्य सरकार ने जनता के टैक्स से वसूले गए पैसों में से करीब 50-60 करोड़ रुपये फूंक डाले। बदले में मिला क्या....सिर्फ आश्वासन। हालांकि सरकार के पास बताने को यह है कि 359 कंपनियों से करार हुए यानी कंपनियां करीब 5.8 लाख करोड़ का निवेश राज्य में करेंगी और खट्टर का दावा है कि करीब 4-5 लाख युवकों को हरियाणा में नौकरियां मिलेंगी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हरियाणा के लाखों युवक रोजगार पा जाएंगे लेकिन पिछली भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार भी अपने 10 साल के कार्यकाल में लाखों युवकों का रोजगार लगाने का वादा करने के बावजूद एक की भी नौकरी नहीं लगा सकी।

हुड्डा के कार्यकाल में झज्जर, सोनीपत, मानेसर, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव में किसानों की जमीन यह कहकर एक्वॉयर की थी कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे लेकिन किसानों की जमीन लेने के बावजूद आज तक किसी किसान के बच्चे की नौकरी नहीं लगी। जमीन से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, मनु चावला, डीएलएफ जैसी कंपनियां मालामाल हो गईं। किसान ने पैसे से बीएमडब्ल्यू और आडि गाड़ी खरीदकर लड़की को दहेज में दे दिया और अब शराब के प्याले से शाम रंगीन कर रहा है। वो पैसे भी एक न एक दिन खत्म होने हैं।

अब कुछ ऐसा ही सब्जबाग लेकर खट्टर भी खुद और अपनी पार्टी को मालामाल करने के लिए हरियाणा में उद्योगपतियों को बुलाने के लिए चारा फेंक रहे हैं। हरियाणा सरकार बताए कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस के कार्यकाल और मौजूदा बीजेपी सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल में हरियाणा के कितने लोगों की नौकरियां लगी हैं।

हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर जो नौकरियां दे भी रहा है वो नौकरियां ज्यादातर कॉल सेंटरों में हैं। स्किल वाली नौकरियां न तो हैं और अगर हैं तो उन पर योग्यता के आधार पर भर्ती होती है, उनमें दूसरे राज्यों से आए हुए लोग ज्यादा भर्ती होते हैं। क्योंकि हरियाणा का युवक तो सरकारी नौकरी के लिए पैदा हुआ है। बहुत हुआ तो सेना और हरियाणा-दिल्ली पुलिस में भर्ती होना उसकी जिंदगी का मकसद रहता है। इसलिए स्किल हासिल करने के लिए न तो सरकार उसे प्रेरित करती नजर आती है और न ही परिवार। सरकारी नौकरी में तनख्वाह के अलावा मोटी रिश्वतत कमाना उसे ज्यादा अच्छा लगता है।

हरियाणा में सरकारी नौकरी देने वाला हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हुड्डा के कार्यकाल में सिर्फ नेताओं और मंत्रियों के बच्चों को नौकरियां देता रहा है। अब पारदर्शिता के नाम पर बीजेपी ने अपने चमचों को इस कमीशन में बैठा दिया है तो नौकरियां फिर से नेताओं, मंत्रियों के बेटों को मिल रही हैं। महा भ्रष्टाचार की वजह से आम आदमी के नसीब में हरियाणा की सरकारी नौकरियां है हीं नहीं। ऐसे में बीजेपी सरकार गुड़गांव में उद्योगपतियों को बुलाकर सम्मेलन करे या फिर रोहतक में करे...हरियाणा में कांग्रेस राज का करप्शन अब बीजेपी नामक दुकान से चलाया जा रहा है। सिर्फ चेहरे बदलें हैं, व्यवस्था वही है।

मुकेश अंबानी के रिलायंस की झज्जर में वापसी

हुड्डा के कार्यकाल में किसान आंदोलन को नजरअंदाज करके भारत के सबसे बड़े अमीर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को झज्जर में एसईजेड (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) बनाने के लिए जमीन सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई गई थी। यह जमीन 8000 एकड़ से ज्यादा थी। चुनाव नजदीक आ गया, राहुल गांधी को ज्ञान हुआ कि किसान नाराज हुए तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो उन्होंने हरियाणा में किसान की जमीन एक्वायर करने की पूरी पॉलिसी बदलवा दी और उसे किसानों के हक में करा दिया। रिलायंस ने फौरन घोषणा की कि राज्य में जो हालात हैं, उस स्थिति में अब वो एसईजेड नहीं बनाएगी और जमीन सरकार को वापस कर रही है। रिलायंस झज्जर से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग खड़ी हुई।....लेकिन ये क्या हुआ...रिलायंस झज्जर में फिर से लौट रही है...और उसे जमीन भी वही मिलने जा रही है, जहां उसे एसईजेड बनाना था। रिलायंस ने अब इसे मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप नाम दिया है। इस टाउनशिप में इलेक्ट्रॉनिक्स और फुटवियर इंडस्ट्रीज रिलायंस की छतरी के नीचे खुलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस टाउनशिप में जिसे फुटवियर या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लगानी है, उसे रिलायंस से लाइसेंस लेना होगा या रिलायंस से वह जगह खरीदनी होगी। हालांकि रिलायंस ने सावधानी बरतते हुए अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। रिलायंस ने गुड़गांव के सम्मेलन में चुपचाप दो करार सरकार से किए लेकिन उसकी खबर फौरन जारी नहीं की गई। लेकिन अब सूचनाएं छनकर बाहर आई हैं।

यहां कुछ सवाल खड़े हो गए हैं...जिनका जवाब हरियाणा की जनता और मजदूर मोर्चा चाहता है...

- **अगर रिलायंस ने एसईजेड बनाने के लिए जो 8000 एकड़ जमीन हुड्डा के कार्यकाल में वापस कर दी थी तो क्या दोबारा रिलायंस को दी गई है।**
- **रिलायंस ने पिछले समझौते का जो उल्लंघन किया है, क्या उसे फिर से जमीन देने का फैसला ठीक है?**
- **कहीं रिलायंस तो डीएलएफ की तर्ज पर अपनी रीयल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी डीलिंग की कंपनी तो नहीं खोलना चाहता है और फिर उस जमीन को महंगे दामों पर बाकी इंडस्ट्री वालों को बेचे। हाल ही में रिलायंस ने रिएल्टी सेक्टर में भी उतरने का फैसला किया है। क्या हरियाणा सरकार ने रिलायंस से यह लिखित में लिया है कि वह झज्जर की टाउनशिप में प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करेगी।**
- **हरियाणा सरकार यह बताए कि रिलायंस को झज्जर के अलावा हरियाणा के और किन शहरों में जमीन दी जा रही है...हरियाणा के लोगों को यह जानने का हक है...**
- **गुड़गांव में सम्मेलन के दौरान सारी कंपनियों के करार को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया तो रिलायंस से हुए करार को मीडिया को क्यों नहीं बताया गया।**

देखना है कि गुड़गांव में हुए सम्मेलन की आड़ में और किसके क्या-क्या हित साधे गए...यह कुछ दिनों में और भी साफ हो जाएगा। सारे मामले में लग तो यही रहा है कि रिलायंस कंपनी हरियाणा में दूसरी डीएलएफ कंपनी की तरह आने वाली है।